सीवरेज प्रणाली - एक ज्वलन्त समस्या

पंकज गर्ग, वैज्ञानिक 'ब'
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान , रूड़की

दुनिया भर में करीब 120 करोड़ लोग शौचालय सुविधा से वंचित हैं । इसमें सर्वाधिक संख्या भारत में है । विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से कराये गये अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि शौचालय का उपयोग न करने वाले लोगों के देश की सूची में यह देश पहले नम्बर पर है । निश्चित है कि इस तरह की रिपोर्ट में यह स्थिति देश के लिए चुनौती है । सवाल यह है कि महाशक्ति बनने की राह में चल रहा भारत इस तरह के मामले में अपनी छवि कैसे सुधारेगा ।

ऐसा नहीं है कि खुले में शौच जाने की परम्परा सदियों से रही हो , प्राचीन काल में भी शौचालयों का उल्लेख मिलता है । इसका इतिहास हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की संस्कृति जितनी पुरानी है । भारत में करीब 66 करोड़ मनुष्य ऐसे हैं जिनके लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है और उन्हें मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ता है । इस तरह भारत की आधी जनसंख्या के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । भारत जैसी स्थिति और देशों में भी है । इस रिपोर्ट में भारत के बाद इंडोनेशिया , इथोपिया और पाकिस्तान का नम्बर आता है । इन्डोनेशिया में लगभग 6.6 करोड़ लोग जन सुविधा से वंचित हैं । इथोपिया में यह संख्या 5.2 करोड़ व पाकिस्तान में 5.0 करोड़ लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । इसी कड़ी में नाइजीरिया , ब्राजील व बांग्ला देश के करोड़ों लोग खुली जगह में शौच जाने के लिए वाध्य हैं।

सैनिटेशन भौतिक अवधारणा का मुख्य तत्व है जो किसी बस्ती की पर्यावरणीय स्थिति का निर्धारण करता है और इसके लिए गहन योजना, विकास एवं प्रबन्धन की आवश्यकता होती है । अनियन्त्रित शहरीकरण ने नगरों के समीप खेती की भूमि को मकानों में बदल दिया है । जहाँ सैनीटेशन की सीवरेज प्रणाली का विकास नहीं हुआ । समुचित शोधन वाली उपयुक्त सीवरेज निकास प्रणाली मुख्य तत्व है जो सन्तुलित तथा व्यवस्थित विकास की पूर्व शर्त है ।

सीवरेज नेटवर्क प्रणाली की विस्तार गति जनसंख्या वृद्धि दर से पिछड़ गयी है जिसके कारण सीवेज नालियों में जाता है और नदी प्रदूषण का कारण बनता है । बस्तियों के निचले

स्थानों में यह तालाब का रूप ले लेता है व महामारी का कारण बनता है । शहरों के विभिन्न हिस्सों में नगर पालिका की सीवरेज प्रणाली कवरेज में असन्तुलन है ।

संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता अभियान

क्या संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता अभियान के लिए सहयोग नहीं दे सकता ? यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है , लेकिन इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है ।

अन्तराष्ट्रीय परोपकारी संगठन "वाटर एड " ने जापान में आयोजित G-8 की बैठक में विश्व नेताओं के लिए इस मसले पर आंकड़े एकत्रित किए थे । उसके अनुसार दुनिया की 40 प्रतिशत आवादी के पास सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है । मलेरिया , एच.आई.वी./एड्स और खसरे से होने वाली कुल मौतों की तुलना में उपरोक्त दूषित वातावरण से कहीं ज्यादा संख्या में बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं । वाटर एड का मानना है कि बेहतर सैनिटेशन की व्यवस्था के चलते 9,10,000 बच्चों की मौत प्रतिवर्ष टाली जा सकती है । इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष डायरिया से होने वाली मौतों में 85 प्रतिशत का सम्बन्ध सैनिटेशन की खराब स्थिति और असुरक्षित पेयजल से है ।

इसमें कोई भी हकीकत नयी नहीं है , फिर भी कुछ साल बाद नई रिपोर्ट जारी होती है और वाटर एड जैसे संगठन अभियान चलाते हैं । वैज्ञानिक उनकी चिन्ता को जायज बताकर बयान जारी करते हैं , पर कारगर कदम नहीं उठाते और इसका परिणाम यह होता है कि समस्या राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मंच पर ज्यों की त्यों रहती है ।

क्या कारण है कि

- पानी और ऊर्जा जैसी अनेक जरूरतों की तुलना में सैनिटेशन के मसले को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है ?
- क्या इसका कारण मध्यम वर्ग के लोग हैं जो शौचालय की सुविधा वाले स्थायी मकानों में रहते हैं और इस कारण सैनिटेशन का कोई मुद्दा नहीं बनता ?
- यह समस्या मूल रूप से गरीबों और बेघर लोगों की है ।
- इस समस्या में सबसे अधिक महिलायें व बच्चे प्रभावित होते हैं ।
- अत्यन्त कमजोर वर्ग के मनुष्य सबसे अधिक प्रभावित होते हैं , जिन लोगों के पास नीति निर्धारण की शक्ति है वे इस मसले पर अधिक ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं करते । इस प्रकार इस मसले को कम प्राथमिकता दी जा रही है ।

फिर सवाल उठता है - क्यों ?

ऐसा क्यों - जब हम एक परमाणु शक्ति के बतौर मान्यता पाना चाहते हैं ।
- जब हम एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में मान्यता पाना चाहते हैं ।
- जब हम अपने शिक्षित और प्रशिक्षित मानव शक्ति पर गर्व करते हैं ।
- जब हम अपने देश में ऑलम्पिक खेलों के आयोजन की क्षमता रखते हैं, तो

क्या हमें सैनिटेशन जैसे महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए ?

स्वच्छ और स्वस्थ जीवन मात्र एक व्यक्तिगत बना दिया गया है । स्वास्थ्य का अर्थ यह लगाया जाता है कि हम क्या खाते हैं , व्यायाम करते , इलात कराते हैं आदि । ऐसे क्षेत्र में जहाँ पीने के पानी की लाइन न हो , सीवरेज नहीं हो , चारों ओर कूड़ा-करकट हो आस-पास का वातावरण आपके स्वच्छ व स्वस्थ रहने की इच्छा को नकारता हो ।

(1) क्या आपके स्कूल में पानी पीने व सैनिटेशन की व्यवस्था है ?
(2) क्या ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं ?
(3) क्या पीने का पानी हर समय आता है ?
(4) क्या हाथ धोने के लिए साबुन है ?

यदि हाँ , तो आप भाग्यशाली हैं । आज हमारे देश में 100 स्कूलों में से 60 स्कूल बिना सैनिटेशन व्यवस्था के कार्य कर रहे हैं । आज हमारे देश में 4,30,610 स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं । इसी कारण लोग अपनी बेटी को शिक्षा देने में असमर्थ हैं । इतना ही नहीं बहुत से स्कूलों में पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है ।

भारत में अरबों लीटर कचरा प्रतिदिन नदियों में बहाया जाता है । इनमें 75 प्रतिशत् इन्सानी गन्दगी व 25 प्रतिशत् भाग औद्योगिक कचरा होता है । नदियों को भारत माता की धमनियों की संज्ञा दी गयी है । आज के युग में भारतीय नदियों के साथ-साथ जीने वाले करोड़ों लोग और उनकी संस्कृतयाँ अभूतपूर्व संकट में हैं । अपने जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ रही नदियां नालों में बदल गयी हैं । इन नदियों में औद्योगिक कचरे का प्लास्टिक कचरा वाकी इन्सानी गन्दगी(सीवरेज) इन नदियों में स्नान करना तो दूर जल से अर्घ्य देना भी दुष्कर काम है । महानगरों का सीवरेज बिना ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सीधे इन नदियों में बहा जा रहा है । वह दिन दूर नहीं जब नदियों का विस्तृत जाल , महामारी का कारण बनेगा ।

*****